पेप्सिकों इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

ग्रॉसरी मार्केट एंड शॉप्स बोर्ड एंड अन्य

(सिविल अपील सं. 9999/2010 आदि)

12 फरवरी, 2016

[कुरियन जोसेफ और रोहिंटन फाली नरीमन, जे.जे.]

महाराष्ट्र माथाडी, हमाल और अन्य मैनुअल श्रमिक (रोजगार और कल्याण विनियमन) अधिनियम, 1969-किराना बाजार या दुकानें असुरक्षित श्रमिक (रोजगार और कल्याण विनियमन) योजना, 1970-पेट्रो-रासायनिक कारखाने में असुरक्षित श्रमिकों और पेयजल और शीतल पेय बनाने वाली कंपनी पर अधिनियम और योजना लागू करना-राज्य सरकार ने आवेदनों को खारिज कर दिया। 1969 के अधिनियम में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जे. ई. 1969 अधिनियम और 1970 की योजना विचाराधीन कारखानों पर लागू थी-राज्य सरकार के आदेशों के खिलाफ रिट याचिकाएं खारिज-अपील पर, याचिका कि 1970 की योजना 1969 के अधिनियम के अधिकार क्षेत्र अधिकारातीत थी; और यह कि अधिनियम और योजना विचाराधीन कारखानों पर लागू नहीं होती थी-अभिनिर्धारित किया गयाः 1970 की योजना का कोई भी हिस्सा 1969 के अधिनियम के अधिकार क्षेत्र अधिकारातीत नहीं है-राज्य ने सही निर्णय लिया कि 1969 का अधिनियम और 1970 की योजना विचाराधीन कारखानों पर लागू थी-उच्च न्यायालय ने राज्य के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया।

शब्द और वाक्यांशः 'स्थापना' का अर्थ। महाराष्ट्र माथाडी, हमाल और अन्य मैनुअल श्रमिक (रोजगार और कल्याण का विनियमन) अधिनियम, 1969 के संदर्भ में।

'किराना'- मतलब का

न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया

सिविल याचिका सं 10000/2010:

1. महाराष्ट्र माथाडी, हमाल और अन्य मैनुअल श्रमिक (रोजगार और कल्याण विनियमन) अधिनियम, 1969 की अनुसूची का खंड 5 एक अवशिष्ट खंड है जो अनुसूची में किसी अन्य प्रविष्टि के दायरे में नहीं आने वाले श्रमिकों द्वारा किए गए लोडिंग, अनलोडिंग आदि के संबंध में कारखानों में रोजगार को शामिल करेगा।मान लीजिए, कारखानों में पेट्रो-रसायनों का निर्माण अनुसूची में प्रविष्टि 4 सहित किसी अन्य प्रविष्टि के दायरे में नहीं आता है।इस कारण से, 1; कारखानों में पेट्रो-रसायनों के निर्माण से संबंधित किराना बाजार या दुकानें असुरक्षित श्रमिक (रोजगार और कल्याण का विनियमन) योजना, 1970 के प्रावधान अवशिष्ट प्रविष्टि यानी 1969 अधिनियम की अनुसूची की वस्तु 5 के दायरे में होंगे। ऐसा होने के कारण, 1970 की योजना का कोई भी हिस्सा 1969 के अधिनियम के अधिकार क्षेत्र अधिकारातीत नहीं है। [पैरा 7] [322-सी-ई]

2. 1970 की योजना का खंड 2 (1) (1) 1969 के अधिनियम की खंड 1 (4 ए) तालिका कॉलम 4 मद 5 के अंतर्गत आता है। यह स्पष्ट है कि "उर्वरकों सहित उत्पाद" अभिव्यक्ति "उर्वरकों सहित रासायनिक उत्पाद" अभिव्यक्ति की तुलना में व्यापक है। 1969 के अधिनियम की शब्दावली विवादित 1970 की योजना की शब्दावली से व्यापक होने के कारण, स्पष्ट रूप से 1970 की योजना जब कारखानों में निर्मित "रासायनिक

उत्पादों" की बात करती है और 1969 के अधिनियम की अनुसूची में प्रविष्टि 5 द्वारा कवर की जाती है, तो यह अभिव्यक्ति "उर्वरकों सहित उत्पाद" होगी।[पैरा 8) [322-ई-जी)

3. "पेट्रो रासायनिक उत्पाद "रासायनिक उत्पादों" की एक प्रजाति होगी। वास्तव में, अपीलकर्ता ने स्वीकार किया है कि वह पॉलीस्टीरिन (दाने) का निर्माण करता है। पॉलीस्टीरिन को बदले में एक सस्ते और कठोर प्लास्टिक के रूप में वर्णित किया गया है जो एक विनाइल बहुलक है।रसायन और पेट्रो रसायन विभाग द्वारा बनाई गई 11 वीं पंचवर्षीय योजना में रसायनों और पेट्रो रसायनों पर कार्य समूह की रिपोर्ट का अवलोकन, यह स्पष्ट है कि न केवल विभिन्न रासायनिक यौगिकों से प्राप्त पेट्रो रसायन हैं, बल्कि यह भी कि पेट्रो रासायनिक निर्माण में अन्य चीजों के अलावा प्लास्टिक का उत्पादन भी शामिल है।अधिनियम की खंड 13 के तहत नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा अपने दिनांकित आदेश में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पेट्रो-रासायनिक उत्पाद रासायनिक उत्पादों की एक प्रजाति हैं और अपीलकर्ता रासायनिक उत्पादों का निर्माण करता है, इसे विकृत नहीं कहा जा सकता है।[पैरा 9,10 और 11] [322-एच; 323-ए, एफ; 324-बी]

4. 1969 के अधिनियम की खंड 3 और 4 एक ऐसी योजना का उल्लेख करती है जो किसी भी अनुसूचित रोजगार या रोजगार में असुरक्षित श्रमिकों के पंजीकरण का प्रावधान करती है (1969 के अधिनियम की खंड 3 (1) के अनुसार)।इसके अलावा, 1969 के अधिनियम की खंड 4 (1) यह भी स्पष्ट करती है कि राज्य सरकार किसी भी अनुसूचित रोजगार या अनुसूचित रोजगारों के समूह के लिए एक या अधिक योजनाएं बना सकती है। इन प्रावधानों को पढ़ने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि एक समग्र योजना हो सकती है जो विभिन्न रोजगारों को अपने दायरे में लेती है जो 1969

के अधिनियम की अनुसूची की एक से अधिक प्रविष्टियों में निहित हो सकते हैं। ऐसा होने के कारण, यह स्पष्ट है कि केवल एक विशेष समग्र योजना को किराने का बाजार या दुकान योजना के रूप में नामित करने से मामला आगे नहीं बढ़ता है।यह स्पष्ट है कि वर्तमान योजना विशेष रूप से 1969 के अधिनियम की अनुसूची में प्रविष्टि 5 द्वारा कवर किए गए रासायनिक उत्पादों का निर्माण करने वाले अपने केन कारखानों के भीतर ले जाती है, और इसलिए यह एक ऐसी योजना होगी जो असुरक्षित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए विभिन्न अनुसूचित रोजगारों और/या अनुसूचित रोजगारों के एक समूह का प्रावधान करती है।यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि 1970 की योजना के किराना बाजार या दुकानों की योजना के रूप में नामकरण पर आधारित हमले को जेल जाना चाहिए।[पैरा 12] [324-एफ-एच; 325-ए]

5. 1969 के अधिनियम की खंड 2 (4), जो "स्थापना" को परिभाषित करती है, में न केवल कोई भी स्थान या परिसर शामिल होगा जिसमें पेट्रो रसायनों का निर्माण किया जा रहा है, बल्कि इसके परिसर भी शामिल होंगे, जिसमें कारखाने के द्वार से परे बल्कि कारखाने के परिसर के भीतर किया गया परिवहन शामिल होगा।यह मामला होने के कारण, यह सामान्य आधार है कि कर्मचारी आवश्यक हैं और अपीलकर्ता द्वारा अपीलकर्ता के उत्पादों को अपीलकर्ता के खरीदारों द्वारा प्रदान किए गए वाहनों पर लोड करने के लिए उपयोग किया जा रहा है।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि कारखानों की विनिर्माण गतिविधियाँ मशीनीकृत हैं और शारीरिक श्रम की कोई आवश्यकता नहीं है।[पैरा 13] [325-बी-सी]

भुवालका स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम बॉम्बे आयरन एंड स्टील लेबर बोर्ड 2009 (16) एससीआर 618:(2010) 2 धारा 273-पर निर्भर।

6. अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों से संकेत लेते हुए, जो एक सामाजिक विधान है और कल्याणकारी विधान के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के विधान का विस्तृत तरीके से अर्थ लगाने के प्रसिद्ध सिद्धांत से, यह माना जाता है कि उच्च न्यायालय को अपने तर्क में दोष नहीं दिया जा सकता है।यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 1970 की योजना का उद्देश्य न केवल नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को काम प्रदान करना है, बल्कि पंजीकृत श्रमिकों को सुविधाएं और लाभ प्रदान करना भी है।बोर्ड द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नियोक्ता से कुल वेतन बिल के 50 प्रतिशत से अधिक शुल्क वसूल कर कर्मचारियों को सबसे अच्छी सुविधाएं और लाभ प्रदान किए जाने हैं।वर्तमान मामले में लेवी राशि 41 प्रतिशत है, जिसका उपयोग न केवल श्रमिकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए किया जाता है, बल्कि उन्हें 1970 की योजना के खंड 43 द्वारा प्रदान किए गए भविष्य निधि और उपदान जैसे अंतिम लाभ देने के लिए भी किया जाता है।[पैरा 16 (327-बी-डीजेजे)

7. इस दलील का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है कि यह अपीलकर्ता के खरीदार हैं न कि अपीलकर्ता कंपनी जो अधिनियम के तहत प्रमुख नियोक्ता है। मामले के तथ्यों में राज्य सरकार के दिनांकित 24.6.2008 आदेश के निष्कर्ष को गलत के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, विकृत की तो बात ही छोड़िए।राज्य सरकार विशेष रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कंपनी में माथाड़ी का काम दो सहकारी समितियों द्वारा किया गया था, जिन्होंने श्रमिकों को नियुक्त करके काम किया था और अपीलकर्ता कंपनी द्वारा उन्हें मुआवजा दिया गया था।[पैरा 19] [328-ई-एफ]

8. भले ही यह माना जाता है कि केंद्रीय संसदीय अधिनियम अर्थात अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 1969 के राज्य अधिनियम को अनिवार्य रूप से निरस्त कर देगा, फिर भी 1970 के अधिनियम की खंड 30 (1) में प्रावधान है

कि 1970 के अधिनियम के प्रावधानों के 1969 के राज्य अधिनियम के साथ कथित रूप से असंगत होने के बावजूद, फिर भी यदि किसी प्रतिष्ठान में नियोजित अनुबंध श्रम उन लाभों के हकदार हैं जो उनके लिए 1970 के अधिनियम के तहत अधिक अनुकूल हैं, तो अनुबंध श्रम अधिक अनुकूल लाभों का हकदार बना रहेगा, भले ही वे केंद्रीय संसदीय अधिनियम के तहत अन्य मामलों के संबंध में भी लाभ प्राप्त करते हों। [पैरा 20] [329-ए-बी]

सिविल याचिका सं : 9999/2010

9. उच्च न्यायालय राज्य सरकार के दिनांक 1 के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करने और अपीलकर्ता कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने में आत्यन्तिक रूप सही था।[पैरा 28] [333-डी]

10. यह याचिका कि न्यायालय को "किराना" शब्द का अर्थ उस तारीख तक खोजना चाहिए जिस दिन अधिनियम का विस्तार किया गया था (यानी 1983), उस क्षेत्र में जिसमें अपीलकर्ता कंपनी का कारखाना स्थित था, कानून में गलत है। 2005 में "किराने का सामान" शब्द, जब अधिनियम को अपीलकर्ता कंपनी पर लागू करने की मांग की गई थी, में अपीलकर्ता कंपनी द्वारा निर्मित शीतल पेय और मध्यम वर्ग और समाज के अमीर वर्गों के बीच दैनिक घरेलू सामान के रूप में बोतलबंद पानी शामिल होगा।[पैरा 27) [332-डी-ई]

वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक और अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण चोपड़ा और अन्य 1962 (3) एस. सी. आर. 146-पर भरोसा किया।

कोलिन्स इंग्लिश डिक्शनरी, तीसरा संस्करण-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

2009 (16) एस. सी. आर. 618 भरोसा किया पैरा4 पर

1962 (3) एस. सी. आर. 146 भरोसा किया पैरा 27

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार न्यायनिर्णयः सिविल याचिका सं 9999/2010

बॉम्बे उच्च न्यायालय के डब्ल्यू. पी. सं. 1931/2009 में दिनांकित 12.02.2009 के निर्णय और आदेश से

के साथ

सीए सं सं. 10000 ऑफ 2010

जे. पी. कामा, वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री कीर्ति चंद्र, अमित ढींगरा, अमनदीप बावा, दिव्यम अग्रवाल, कुना!मिमानी, धीरज नायर, मिस. दुआ एसोसिएट्स, अधिवक्ता अपीलार्थियों के लिए।

आर. बसंत, ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुशी!करंजकर, के. एन. राय, श्रीमती जयश्री वाड, आशीष वाड, जयंत बी. शालिग्राम, सुश्री परोमिता मजूमदार, सुश्री जया खन्ना, (मिस के लिए। जे. एस. वाड एंड कंपनी), जे. इतेंद्र कुमार, सुनील एम. चिंचवड़कर, नितिन एस. तंबवेकर, बी. एस. साई, के. राजीव, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, अधिवक्ता।प्रतिवादीओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे. 1.इन अपीलों में महाराष्ट्र माथाडी, हमाल और अन्य मैनुअल श्रमिक (रोजगार और कल्याण का विनियमन) अधिनियम, 1969 (इसके बाद "1969 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों की व्याख्या शामिल है, जिसे किराना बाजार या दुकानें असुरक्षित श्रमिक (रोजगार और कल्याण का विनियमन)

योजना, 1970 (इसके बाद "1970 योजना" के रूप में संदर्भित) के साथ पढ़ा जाता है। सिविल याचिका सं में निर्णय के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य। 20 में से 0000 (सुप्रीम पेट्रो-केम लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य) यह है कि उक्त 1969 के अधिनियम की खंड 5 के तहत, यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई योजना असुरक्षित श्रमिकों के किसी भी वर्ग पर लागू होती है, तो मामला राज्य सरकार को भेजा जाएगा और राज्य सरकार का निर्णय जो खंड 14 के तहत गठित सलाहकार समिति से परामर्श करने के बाद लिया जाएगा, अंतिम होगा।दिनांक 24.6.2008 के एक आदेश द्वारा, राज्य सरकार ने अपीलार्थियों की प्रस्तुतियों के साथ-साथ बोर्ड की प्रस्तुतियों को संदर्भित करने के बाद कहाः-

> "4.सरकार ने समग्र स्थिति का विश्लेषण किया है, संगठन के दिनांकित दस्तावेज़ आवेदन और उत्पाद और उसके कच्चे माल के बारे में जानकारी दी है। सरकार निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंची हैः
>
> ए. कंपनी पॉलीस्टीरिन का निर्माण कर रही है।
>
> बी. स्टाइरीन और पॉलीब्यूटाडिन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। पॉलीब्यूटाडिन रबर के रूप में आता है और यह प्राकृतिक रबर नहीं है।
>
> ग. पॉलीस्टीरिन एक कठोर प्लास्टिक है।
>
> घ. पॉलीस्टीरिन एक पेट्रोकेमिकल उत्पाद नहीं है बल्कि एक रासायनिक उत्पाद है।

ई. यहां तक कि पॉलीस्टीरिन निर्माण को पेट्रोकेमिकल उत्पादन माना जाता है, यह अंत में केवल एक रासायनिक उत्पादन है।उत्पाद के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री भी रासायनिक है।

च. माथाडी अधिनियम में कोई लिखित संदर्भ नहीं है कि पेट्रोकेमिकल को अधिनियम से बाहर रखा जाना चाहिए, लेकिन रसायन में ही सब कुछ शामिल है।

छ. माथाडी अधिनियम और योजना श्रमिकों की बेहतरी के लिए है और योजना का उद्देश्य रासायनिक विनिर्माण कंपनियों पर लागू करना है।योजना में यह उल्लेख नहीं है कि पेट्रोकेमिकल उत्पादों को बाहर रखा जाना चाहिए और चूंकि योजना में पेट्रोकेमिकल का उल्लेख नहीं है, इसलिए यह योजना उक्त संगठन पर लागू नहीं है, यह स्वीकार्य नहीं है।

5. इस स्थिति में समिति और सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि किराने का बाजार और दुकानें असुरक्षित श्रमिक (रोजगार और कल्याण विनियमन) अधिनियम । 970 सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड पर लागू होता है।

6. कंपनी में रासायनिक उत्पाद और उसके कच्चे माल को उतारने का काम किया जाता है।और इस संबंध में कंपनी में माथाडी तरह का काम किया जाता है।जैसा कि कंपनी ने कहा कि यह काम दो सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है।ये समितियाँ श्रमिकों को नियुक्त करके काम करती हैं और कंपनी से मुआवजा प्राप्त करती हैं।कंपनी का कहना है कि इन कर्मचारियों को भविष्य निधि और अन्य

सुविधाएं मिलती हैं।लेकिन मंडल द्वारा 20.09.2006 पर दायर रिपोर्ट में यह बयान साबित नहीं हुआ है।2006 (3) सी. एल. आर. पी. जी. 999 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार, कंपनी क्या कह रही है, इसका कोई अर्थ नहीं है।इसके बजाय यह साबित करता है कि उक्त कंपनी में मथादी तरह का काम होता है।

8. इस स्थिति में महाराष्ट्र माथाडी हमाल और अन्य मैनुअल श्रमिक (रोजगार और कल्याण का विनियमन) अधिनियम 1969, किराने का बाजार या दुकानें असुरक्षित श्रमिक (रोजगार और कल्याण का विनियमन) योजना 970 उक्त संगठन पर लागू होती है।इसलिए, माथाडी अधिनियम की खंड 5 के तहत दिए गए आवेदन को सरकार द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

2. उक्त आदेश को बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी।रिट याचिका को विवादित फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया था।nt दिनांकित I 0.2.2009 धारण करने के बादः-

"4.विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को पचाना मुश्किल है।मूल रूप से, हम जो पाते हैं वह यह है कि याचिकाकर्ता पॉलीस्टेरीन का निर्माण कर रहे हैं और पॉलीस्टेरीन स्टाइरीन और पॉलीब्यूटाडिन का एक संयोजन है। पॉलीब्यूटाडिन रबर के रूप में आता है और यह एक पेट्रोकेमिकल नहीं है, हालांकि यह एक प्राकृतिक रबर नहीं है।स्टाइरीन पेट्रोकेमिकल के उप-उत्पादों में से एक है जिसका उपयोग याचिकाकर्ता द्वारा पॉलीस्टेरीन के निर्माण के लिए किया जाता है।इसलिए, याचिकाकर्ता किसी भी पेट्रोकेमिकल का निर्माण नहीं कर रहे हैं, लेकिन

पेट्रोकेमिकल के उपोत्पाद में से एक का उपयोग याचिकाकर्ताओं द्वारा पॉलीस्टेरीन और पॉलीस्टेरीन के निर्माण के लिए किया जाता है जो कठोर प्लास्टिक है।

5. इन सभी पहलुओं पर सरकारी अधिकारियों द्वारा विचार किया गया है और उसके बाद अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला है कि याचिकाकर्ता पेट्रोकेमिकल्स के साथ काम नहीं कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने प्रस्तुत किया हैःहम प्राधिकरण के निष्कर्षों से सहमत हैं।यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता पेट्रोकेमिकल्स में काम कर रहे हैं, फिर भी अधिनियम उन पर लागू होगा क्योंकि ऊपर उल्लिखित इस आवेदन खंड में उपयोग किए गए शब्द खाद सहित उत्पाद हैं और इस तरह, हर प्रकार के उत्पादन को शामिल किया गया है।ध्यान दें योग्य बात यह है कि जो खाद यूरिया आदि की तरह होती हैं, वे भी पेट्रोकेमिकल्स से व्युत्पन्न होती हैं और इस प्रकार समावेशी खंड द्वारा जिन खादों को बचाया जा सकता था, उन्हें शायद वहां शामिल किया गया होगा।अब तक, "उत्पाद" शब्द का उपयोग विधानमंडल द्वारा अपने ज्ञान में अपने सभी संज्ञानात्मक बदलावों के साथ किया गया है और इसका सीमित अर्थ होने की व्याख्या नहीं की जा सकती है।हम जो पाते हैं वह यह है कि पेट्रोकेमिकल रसायन का एक हिस्सा है। रासायनिक उत्पत्ति है जबकि पेट्रोकेमिकल उक्त उत्पत्ति की प्रजाति है और इस प्रकार यदि रासायनिक उद्योग को शामिल किया जाता है तो यह मानना मुश्किल है कि पेट्रोकेमिकल उद्योग शामिल नहीं हैं।

6. इस बात पर गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस उद्योग में मठड़ी जो काम कर रहे हैं, वह उपलब्ध है या नहीं।यदि उस उद्योग में मठड़ियों का काम उपलब्ध है तो केवल इसलिए कि उद्योग कुछ अलग पहलू में काम कर रहा है, वह काम कुछ अन्य असंगठित श्रमिकों को नहीं दिया जा सकता है।यह सुनिश्चित करने के बाद कि उद्योग कानून द्वारा कवर किया गया है, मूल परीक्षा यह पता लगाना है कि मठड़ियों का काम उपलब्ध है और यदि यह उपलब्ध है, तो अधिनियम और योजना उद्योग पर लागू होगी।यह विवादित नहीं है कि मठड़ी का काम उपलब्ध नहीं है।एकमात्र भेद जो करने का प्रयास किया गया था वह पेट्रोकेमिकल्स के संबंध में था और इसलिए, अधिनियम लागू नहीं होता है, जिसे हम ऊपर बताए गए कारणों से पहले ही खारिज कर चुके हैं।हम पाते हैं कि सरकार ने खंड 5 के तहत मामले का सही फैसला किया है और इस अदालत के हाथों किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

3. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जे. पी. कामा ने तर्क दिया है कि 1969 का अधिनियम केवल उन रोजगारों पर लागू होता है जो अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।जैसा कि अनुसूची की मद 4 में किराने के बाजारों या दुकानों का उल्लेख किया गया है, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, कारखानों में रोजगार जो केवल उक्त अनुसूची की मद 5 में होता है, संभवतः आकर्षित नहीं किया जा सकता है क्योंकि मद 5 केवल उन प्रतिष्ठानों की बात करता है जो अनुसूची में किसी अन्य प्रविष्टि द्वारा शामिल नहीं हैं।चूंकि वर्तमान मामले में 1970 की योजना किराने के बाजारों या दुकानों में रोजगार से संबंधित एक योजना है, इसलिए अनुसूची की मद 5 आकर्षित नहीं होती है, और 1970 की योजना 1969 के अधिनियम के दायरे

अधिकारातीत है क्योंकि यह उन कारखानों में रोजगार का प्रावधान करती है जो रासायनिक उत्पादों का निर्माण करते हैं और उक्त आई 969 अधिनियम की अनुसूची की प्रविष्टि 5 द्वारा कवर किए जाते हैं। उन्होंने 1969 के अधिनियम की खंड 1 (4ए) का भी उल्लेख करते हुए कहा कि जहां तक रायगढ़ जिले के कारखानों में रोजगार का संबंध है, खंड 1 (4ए) से जुड़ी तालिका के कॉलम 4 में आइटम 5 "रंगीन रसायनों" और "उर्वरकों सहित उत्पादों" की बात करता है, न कि "रासायनिक उत्पादों" की।ऐसा होने पर, किसी भी मामले में रासायनिक उत्पाद खंड 1 (4ए) के बाहर हैं, और 1970 की योजना जहां तक यह खंड 2 (1) (टी) "रासायनिक उत्पादों" के तहत इसके भीतर शामिल करने का तात्पर्य है, इसलिए खंड 1 (4ए) के अधिकार अधिकारातीत है।इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अपीलार्थी के कारखाने में जो कथित रूप से निर्मित किया जाता है वह पेट्रोकेमिकल है न कि रसायन।उन्होंने कई दस्तावेजों का उल्लेख किया है जिनमें विभिन्न लाइसेंस और अधिकारियों के पत्र शामिल हैं जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपीलार्थी के कारखाने में जो बनाया जाता है वह केवल पेट्रोकेमिकल है।इस कारण से भी, पेट्रोकेमिकल रसायन नहीं होने के कारण 1969 के अधिनियम या 1970 की योजना के दायरे में नहीं होंगे।उन्होंने 1969 के अधिनियम की खंड 4 (1) (बी) का उल्लेख करते हुए आगे तर्क दिया कि यदि 1970 की योजना को कारखानों में निर्मित पेट्रो रसायनों पर लागू किया जाना है, तो ऐसा करने का एकमात्र तरीका यह है कि यदि अधिकांश नियोक्ताओं या श्रमिकों द्वारा मांग या अनुरोध किया जाता है कि किराने के बाजारों या दुकानों की योजना के प्रावधानों को किसी अन्य अनुसूचित रोजगार पर लागू किया जाना चाहिए-यानी कारखानों में पेट्रो रसायनों का निर्माण, और यह नियोक्ताओं और श्रमिकों के परामर्श के बाद ही है कि राज्य सरकार 1970 की योजना के प्रावधानों को अपीलकर्ता के पेट्रो रसायन बनाने वाले कारखाने पर लागू कर सकती है।ऐसा न किए जाने पर 1970 की योजना अपीलकर्ता

पर लागू नहीं हो सकती है।विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि वास्तव में नियोक्ता द्वारा नियोक्ता के कारखाने से खरीदार के परिसर तक परिवहन का कोई काम नहीं किया जाता है।उन्होंने तर्क दिया कि कारखाना बड़े पैमाने पर मशीनीकृत था और कारखाने में निर्मित पेट्रो रासायनिक उत्पादों को खरीदारों द्वारा अनुबंध श्रमिकों को नियुक्त करके उठाया जाता था जिसे खरीदारों द्वारा स्वयं व्यवस्थित किया जाता था। ऐसा होने पर, 1969 के अधिनियम और 1970 की योजना का अपीलार्थी के कारखाने पर कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।

4. प्रतिवादी-बोर्ड की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री एस. चिंचवाडकर ने श्री कामा की प्रत्येक दलील का विरोध किया है।1969 के अधिनियम की अनुसूची में दिखाई देने वाली श्री चिंचवाड़कर प्रविष्टि 5 एक अवशिष्ट प्रविष्टि है जो उन सभी रोजगारों को लेती है जो अनुसूची की किसी भी अन्य वस्तु के तहत किसी भी योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, और चूंकि कारखानों में निर्मित पेट्रो रसायन किसी भी अन्य वस्तु के अंतर्गत नहीं आते थे, इसलिए वे अवशिष्ट प्रविष्टि के अंतर्गत आते हैं।इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, योजना का नामकरण तब तक अप्रासंगिक है जब तक कि 1970 की योजना के प्रावधान वास्तव में कारखानों में की गई अपीलार्थी की गतिविधियों को शामिल करते हैं।उन्होंने आगे 1969 के अधिनियम की धारा 3 और 4 का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि एक समग्र योजना हो सकती है जिसमें कई अनुसूचित रोजगारों या रोजगारों के समूहों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, जो वर्तमान मामले में किया गया है।उन्होंने खंड I (4ए) के संदर्भ में यह भी तर्क दिया कि कॉलम 4 में आइटम 5 जब "उर्वरकों सहित उत्पादों" का उल्लेख किया जाता है तो इसमें रासायनिक उत्पादों सहित सभी उत्पाद शामिल होंगे, और इसलिए 1970 की योजना 1969 के अधिनियम के अंतर्गत आती है। उन्होंने राज्य सरकार के आदेश का भी उल्लेख किया, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और बरकरार रखा

गया था, ताकि यह दिखाया जा सके कि राज्य सरकार ने 1969 के अधिनियम की खंड 5 के तहत अपना दिमाग लगाया था, और इस तरह के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।उन्होंने हमें खंड 2 (4) में निहित "प्रतिष्ठान" की परिभाषा का भी उल्लेख किया जिसका अर्थ होगा "कोई भी स्थान या परिसर जिसमें उसका परिसर भी शामिल है जिसमें कोई अनुसूचित रोजगार किया जा रहा है।"उनके अनुसार, चूंकि अपीलकर्ता के उत्पाद को कारखाने के परिसर से उठाया जा रहा था, इसलिए अपीलकर्ता 1969 के अधिनियम और 1970 की योजना के दायरे में आएगा।उन्होंने अपने प्रस्ताव को पुष्ट करने के लिए भुवाल्का स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम बॉम्बे आयरन एंड स्टील लेबर बोर्ड, (2010) 2 एस. सी. सी. 273 का भी कुछ विस्तार से उल्लेख किया कि इस न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का अनुसरण करते हुए 1969 के अधिनियम को एक कल्याणकारी कानून के रूप में माना है, और इसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि नियोक्ताओं को उक्त अधिनियम द्वारा परिभाषित श्रमिकों के इस वर्ग के लिए अपने सामाजिक दायित्वों का एहसास करना चाहिए, जो गैर-संरक्षित श्रमिक हैं।

5. हमने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना है।हमारे सामने विवाद के गुण-दोष में प्रवेश करने से पहले, हम 1969 के अधिनियम और उसके तहत बनाई गई 1970 की योजना के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करना चाहेंगे।1969 के अधिनियम का लंबा शीर्षक इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यह उस उद्देश्य को निर्धारित करता है जिसके लिए 1969 के अधिनियम को अधिनियमित किया गया था, और यह इस प्रकार हैः-

"महाराष्ट्र राज्य में कुछ रोजगारों में नियोजित असुरक्षित शारीरिक श्रमिकों के रोजगार को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम, ताकि ऐसी रोजगारों में उनकी पर्याप्त आपूर्ति और उचित और पूर्ण उपयोग के लिए और उससे जुड़े मामलों के लिए प्रावधान किया जा सके।चूंकि, कुछ रोजगारों में लगे हुए असुरक्षित शारीरिक श्रमिकों जैसे कि माथाड-1, हमाल आदि के रोजगार को विनियमित करना, उनके रोजगार के नियमों और शर्तों के लिए बेहतर प्रावधान करना, उनके कल्याण के लिए और स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों के लिए जहां ऐसे रोजगारों के लिए इन उपायों की आवश्यकता होती है; ऐसी नौकरियों में ऐसे श्रमिकों को पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और उनका पूर्ण और उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करना ताकि ऐसी बेरोजगारी को रोका जा सके; इन और इसी तरह के उद्देश्यों के लिए, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में इन रोजगारों के संबंध में और (जहां आवश्यक हो) बोर्डों की स्थापना का प्रावधान करना; और उपरोक्त मामलों से जुड़े उद्देश्यों के लिए प्रावधान करना; यह एतद्द्वारा बीस में अधिनियमित किया गया है।

इन अपीलों पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक अधिनियम की धाराएं बी नीचे दी गई हैं और निम्नानुसार पढ़ी जाती हैंः

"I. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार, अनुप्रयोग और प्रारंभ-

(3) यह अनुसूची में निर्दिष्ट रोजगारों पर लागू होता है।

(4क) उप-धारा (4) और सरकारी अधिसूचना में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उद्योग और श्रम विभाग, सं। यूएमए। 1272/लैब-IV,

दिनांक 28 मार्च 1972, यह अधिनियम नीचे दी गई तालिका के कॉलम 2 में निर्दिष्ट क्षेत्रों में तारीखों पर और कॉलम 3 और 4 में निर्दिष्ट कॉलम में निर्दिष्ट रोजगारों के संबंध में क्रमशः उक्त तालिका में प्रत्येक मुकदमा क्षेत्रों के खिलाफ लागू हुआ माना जाएगा।

क्रमांक न. 1	क्षेत्र 2	दिनांक 3	रोजगार का नाम 4
	(क) 1 ठाणे जिले के ठाणे और कल्याण तालुका; और 1 कुलाबा (अब रायगढ़) जिले के पनवेल तालुका) (ख) ठाणे जिले के 1 ठाणे और कल्याण तालुका और पनवेल तालुका को छोड़कर पूरे ठाणे और रायगढ़ जिले।1 एच रायगढ़ जिला	26 दिसम्बर 1979 1 अगस्त 1983	(I) किराने के बाजार या दुकानों में रोजगार, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टैकिंग, कैनिंग, वजन, मापने (भरने, सिलाई, सफाई) या इस तरह के कार्यों के लिए प्रारंभिक कार्य सहित इस तरह के कार्यों के संबंध में। (2) बाजारों और अन्य प्रतिष्ठानों में रोजगार, सोडा ऐश की लोडिंग, लोडिंग, स्टैकिंग, कैनिंग, वजन, माप (भरना, सिलाई, 9 जॉर्टिंग, सफाई), कोयला-तार, चूने, रंगीन रसायन, उर्वरकों सहित रासायनिक उत्पाद, बारूदीने के थैले, कॉयर की रस्सियां, रस्सियां, चटाई, हेसियन कपड़ा, हेसियन याम, ऑयल केक, इल स्क चुनी और चल-

			या इस तरह के कार्यों के लिए तैयारी या आनुषंगिक कार्य सहित अन्य कार्य। (3) प्याज में रोजगारः:आलू का थोक विपणन ऐसे अन्य कार्यों की लोडिंग, अनलोडिंग, स्टैकिंग ले जाने, वजन, माप (भरने, सिलाई, छँटाई, सफाई) के संबंध में किया जाता है, जिसमें इस तरह के कार्यों के लिए प्रारंभिक या आनुषंगिक कार्य शामिल हैं। (4) किराने के उत्पादों का निर्माण करने वाले कारखानों और मिलों में रोजगार यदि ऐसा रोजगार लोडिंग, अनलोडिंग, स्टैकिंग, सीए ट्राइंग, वेट, माप (भरना, सिलाई, छँटाई, सफाई) या इस अधिनियम की अनुसूची में प्रविष्टि 5 द्वारा कवर किए गए श्रमिकों द्वारा किए गए ऐसे कार्यों की तैयारी या आकस्मिक कार्य सहित ऐसे अन्य कार्यों से जुड़ा है। (5) उर्वरकों सहित रंगीन रसायनों, उत्पादों का निर्माण करने वाले कारखानों और मिलों में रोजगार, यदि ऐसा रोजगार लोडिंग, अनलोडिंग, स्टैकिंग, ले जाने, वजन, माप

			(सिलाई भरने, छँटाई, सफाई) या इस अधिनियम की अनुसूची 1 में प्रविष्टि 5 द्वारा कवर किए गए श्रमिकों द्वारा किए गए ऐसे कार्यों की तैयारी या आकस्मिक कार्य सहित ऐसे अन्य कार्यों के संबंध में है।

2. परिभाषाएँ।

(3) ""नियोक्ता" से ठेकेदार द्वारा या उसद्वारा से लगाए गए किसी भी असुरक्षित श्रमिकों के संबंध में, प्रमुख नियोक्ता और किसी अन्य असुरक्षित श्रमिक के संबंध में, वह व्यक्ति जिसका प्रतिष्ठान के मामलों पर अंतिम नियंत्रण होता है, और इसमें कोई अन्य व्यक्ति शामिल होता है जिसे ऐसे प्रतिष्ठान के कार्य सौंपे जाते हैं, चाहे वह व्यक्ति एजेंट, प्रबंधक कहा जाए या अनुसूचित रोजगार में प्रचलित किसी अन्य नाम से पुकारा जाए।

(4) ""प्रतिष्ठान" से कोई भी स्थान या परिसर अभिप्रेत है, जिसमें उसका परिसर भी शामिल है, जिसमें या जिसके किसी भाग में कोई अनुसूचित रोजगार किया जा रहा है या सामान्य रूप से किया जा रहा है;

(7) ""प्रमुख नियोक्ता" से ऐसा नियोक्ता अभिप्रेत है जो किसी भी अनुसूचित रोजगार में ठेकेदार द्वारा या उसद्वारा से असुरक्षित श्रमिकों को नियुक्त करता है;

(9) "अनुसूचित रोजगार "से यहाँ अनुसूची में निर्दिष्ट कोई भी रोजगार या ऐसे रोजगार का हिस्सा बनने वाली कोई प्रक्रिया या कार्य शाखा अभिप्रेत है;

(10) ""योजना" से इस अधिनियम के तहत बनाई गई योजना अभिप्रेत है;

(11) "असुरक्षित श्रमिक का अर्थ है एक शारीरिक कार्यकर्ता जो किसी अनुसूचित रोजगार में लगा हुआ है या लगा हुआ है;

(12) ""कर्मचारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अनुसूचित रोजगार में शारीरिक कार्य करने के लिए सीधे या किसी एजेंसी द्वारा से, चाहे मजदूरी के लिए हो या नहीं, नियुक्त किया गया है या नियुक्त किया जाना है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो किसी नियोक्ता या ठेकेदार द्वारा नियोजित नहीं है, लेकिन नियोक्ता या ठेकेदार की अनुमति से या उसके साथ समझौते के तहत काम कर रहा है; लेकिन इसमें नियोक्ता के परिवार के सदस्य शामिल नहीं हैं।

3. असुरक्षित श्रमिकों का नियमित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं।-

(I) अनुसूचित रोजगारों में असुरक्षित श्रमिकों की पर्याप्त आपूर्ति और पूर्ण और उचित उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, और सामान्य रूप से ऐसे श्रमिकों के रोजगार के नियमों और शर्तों के लिए बेहतर प्रावधान करने के लिए राज्य सरकार किसी योजना के माध्यम से किसी भी अनुसूचित रोजगार या रोजगार में नियोक्ताओं और असुरक्षित श्रमिकों के पंजीकरण का प्रावधान कर सकती है, और पंजीकृत असुरक्षित श्रमिकों के काम के नियमों और शर्तों का प्रावधान कर सकती है, और ऐसे रोजगारों में सामान्य कल्याण का प्रावधान कर सकती है।

4. योजना बनाना, उसमें बदलाव करना और उसे रद्द करना।-

(I) राज्य सरकार, सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पिछले प्रकाशन की शर्त के अधीन, अधिसूचना में निर्दिष्ट एक या अधिक क्षेत्रों में किसी भी अनुसूचित रोजगार या अनुसूचित रोजगारों के समूह के लिए एक या अधिक योजनाएं बना सकती है और उसी तरह अपने द्वारा

बनाई गई किसी भी योजना के लिए किसी अन्य योजना में जोड़, संशोधन, परिवर्तन या प्रतिस्थापन कर सकती हैः

बशर्ते कि ऐसी कोई अधिसूचना तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक महीने की अवधि समाप्त न हो जाएः

बशर्ते कि राज्य सरकार

(क) यदि वह आवश्यक समझता है, या

(ख) यदि किसी अन्य अनुसूचित रोजगार में अधिकांश नियोक्ताओं या श्रमिकों द्वारा यह मांग या अनुरोध किया जाता है कि किसी अनुसूचित रोजगार या उसके किसी भाग के लिए इस प्रकार बनाई गई किसी योजना के प्रावधानों को ऐसे अन्य अनुसूचित रोजगार पर लागू किया जाना चाहिए, तो आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे अनुसूचित रोजगार में नियोक्ताओं और श्रमिकों से परामर्श करने के बाद, ऐसी योजना या उसके हिस्से के प्रावधानों को ऐसे अनुसूचित रोजगार पर ऐसे संशोधनों, यदि कोई हों, के साथ लागू करें, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाएं।

(2) बॉम्बे जनरल क्लॉज एक्ट, 1904 की खंड 24 के प्रावधान, उप खंड (I) द्वारा दी गई शक्ति के प्रयोग पर लागू होंगे क्योंकि वे महाराष्ट्र अधिनियम द्वारा दिए गए शक्ति के प्रयोग पर लागू होते हैं जो पिछले प्रकाशन की शर्त के अधीन नियम बनाने के लिए होती है।

5. योजना के अनुप्रयोग के संबंध में विवाद।- यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई योजना असुरक्षित एफ श्रमिकों या नियोक्ताओं के किसी भी वर्ग पर लागू होती है, तो मामला राज्य सरकार को भेजा जाएगा और इस प्रश्न पर राज्य सरकार का

निर्णय, जो खंड 14 के तहत गठित सलाहकार समिति से परामर्श करने के बाद लिया जाएगा, अंतिम होगा।

अनुसूची

4. किराने के बाजारों या दुकानों में रोजगार, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टैकिंग, ले जाने, वजन, मापने, फाइलिंग, सिलाई, छँटाई, सफाई या ऐसे अन्य कार्यों के संबंध में जिसमें इस तरह के कार्यों के लिए प्रारंभिक या आकस्मिक कार्य शामिल हैं।

5. बाजार, और कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में रोजगार, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टैकिंग, वजन, माप, फाइलिंग, सिलाई, तो 11 के संबंध में।सफाई या इस अनुसूची में किसी अन्य प्रविष्टि के दायरे में नहीं आने वाले श्रमिकों द्वारा किए गए ऐसे कार्यों के लिए यॉर्क प्रारंभिक या आनुषंगिक सहित ऐसा अन्य यॉर्क।

6. 1970 की योजना के प्रावधान, जहां तक वे वर्तमान अपीलों में निर्णय के लिए प्रासंगिक हैं।यहाँ नीचे दिए गए हैं और निम्नानुसार पढ़े जाते हैंः

> "स. यू.डब्ल्यू.ए-1469।(जीआर) एल 60783/एलएबी-IV:- महाराष्ट्र माथाडी, हमाल और अन्य मैनुअल श्रमिक (रोजगार और कल्याण विनियमन) अधिनियम की खंड 4 की उप-खंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। 1969 (माह. 1969 का XXX) और उस ओर से इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों में से महाराष्ट्र सरकार सलाहकार समिति के परामर्श के बाद, लोडिंग के संबंध में किराने के बाजारों और दुकानों में रोजगार के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है।उतारना।स्टैक करना, ले जाना।इस योजना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों में ऐसे कार्यों के

लिए प्रारंभिक या आनुषंगिक कार्य सहित वजन, माप या ऐसा अन्य कार्य, जो उक्त खंड 4 की उप-खंड (I) द्वारा आवश्यकतानुसार पहले प्रकाशित किया गया हो, अर्थात्ः-

2. वस्तुएँ और अनुप्रयोगः-

(I) वस्तुएँः- इस योजना का उद्देश्य इन क्षेत्रों में कार्यरत असुरक्षित श्रमिकों की पर्याप्त आपूर्ति और पूर्ण और उचित उपयोग सुनिश्चित करना है -

(क) लोडिंग, अनलोडिंग के संबंध में किराने का बाजार या दुकानें। स्टैकिंग।ले जाना, वजन करना।मापना [भरना।सिलाई करना।छँटाई। सफाई] या इस तरह के कार्यों के लिए प्रारंभिक या आनुषंगिक कार्य सहित ऐसा अन्य कार्यः

(ख) लोडिंग के संबंध में बाजार और अन्य प्रतिष्ठान।उतारना।स्टैकिंग। ले जा रहे हैं।सोडा ऐश, कोलटार, चूने, रंग रसायनों का वजन, माप (भरना, सिलाई, छँटाई, सफाई)।उर्वरक, बारूदीने के थैले, कॉयर की रस्सियाँ, रस्सियाँ, 111 ए. टी. सहित रासायनिक उत्पाद।हेसियन, कपड़ा।हेसियन धागा, तेल, केक, भूसी।चूनी, चाला या ऐसा अन्य कार्य जिसमें कार्य के कुशल प्रदर्शन के लिए और आम तौर पर ऐसे श्रमिकों के रोजगार के नियमों और शर्तों के लिए बेहतर प्रावधान करने और उनके सामान्य कल्याण के लिए प्रावधान करने के लिए अनुसूची में किसी अन्य प्रविष्टि द्वारा कवर नहीं किए गए श्रमिकों द्वारा किए गए ऐसे संचालन के लिए प्रारंभिक या आनुषंगिक कार्य शामिल हैं।

(ग) लोडिंग, अनलोडिंग, स्टैकिंग, कैनिंग, वजन मापने [भरने, सिलाई, छँटाई, सफाई], या ऐसे अन्य कार्यों के संबंध में प्याज और आलू थोक बाजार, जिसमें इस तरह के कार्यों के लिए तैयारी या आकस्मिक कार्य शामिल हैं।

(घ) किराने के उत्पादों का निर्माण करने वाले कारखाने और मिलें यदि ऐसा रोजगार लोडिंग, अनलोडिंग, स्टैकिंग, ले जाने, वजन करने, मापने, [भरने, सिलाई, छँटाई, सफाई] या ऐसे अन्य काम से जुड़ा है, जिसमें कार्य की तैयारी या अधिनियम की अनुसूची में प्रविष्टि 5 द्वारा कवर किए गए श्रमिकों द्वारा किए गए ऐसे कार्यों के लिए आकस्मिक कार्य शामिल हैं;

(ई) किराने की वस्तुओं की लोडिंग, अनलोडिंग, स्टैकिंग, ले जाने, वजन करने, मापने (भरने, सिलाई, छँटाई, सफाई) के संबंध में रेलवे यार्ड और माल शेड या ऐसे अन्य कार्य जो रेलवे प्राधिकरणों द्वारा नियोजित नहीं किए गए श्रमिकों द्वारा ऐसे कार्यों की तैयारी या आनुषंगिक हैं और

(च) लोडिंग, अनलोडिंग, स्टैकिंग, ले जाने, वजन करने, मापने (भरने, सिलाई, छँटाई, सफाई) के संबंध में उर्वरकों सहित रंगीन रसायनों, रसायन उत्पादों का निर्माण करने वाले कारखाने और मिलें या ऐसे अन्य कार्य जिसमें उक्त अधिनियम की अनुसूची में प्रविष्टि 5 द्वारा कवर किए गए श्रमिकों द्वारा किए गए ऐसे संचालन की तैयारी या आकस्मिक कार्य शामिल हैं;

42. योजना के संचालन की लागत और पंजीकृत श्रमिकों को सुविधाओं और लाभों का प्रावधान -

(I) इस योजना के संचालन और अधिनियम और इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न लाभ, सुविधाएं और सुविधाएं प्रदान करने की लागत का भुगतान पंजीकृत नियोक्ताओं द्वारा बोर्ड को किए गए भुगतान से किया जाएगा।प्रत्येक पंजीकृत।नियोक्ता बोर्ड को अपने द्वारा आवंटित और नियुक्त पंजीकृत श्रमिकों के संबंध में शुल्क के रूप में ऐसी राशि का भुगतान करेगा जो बोर्ड समय-समय पर पंजीकृत नियोक्ता को सार्वजनिक सूचना या लिखित आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे और इस तरह से और इस तरह से।समय जो बोर्ड निर्देशित करे।

(2) यह निर्धारित करने के लिए कि उपखंड (I) के तहत पंजीकृत नियोक्ताओं द्वारा क्या भुगतान किया जाना है, बोर्ड विभिन्न श्रेणियों के काम या पंजीकृत श्रमिकों के लिए शुल्क की अलग-अलग दर निर्धारित कर सकता है, बशर्ते कि शुल्क इस तरह से निर्धारित किया जाए कि शुल्क की समान दर उन सभी पंजीकृत नियोक्ताओं पर लागू होगी जो समान परिस्थितियों में हैं।

(3) बोर्ड राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कुल मजदूरी बिल के पचास प्रतिशत से अधिक किसी भी शुल्क को मंजूरी नहीं देगाः

(4) एक पंजीकृत नियोक्ता मांग पर बोर्ड को जमा के माध्यम से भुगतान करेगा या उपखंड (I) में निर्दिष्ट राशि के देय भुगतान के लिए ऐसी अन्य प्रतिभूति प्रदान करेगा, जिसे बोर्ड आवश्यक समझे।

(5) सचिव समय-समय पर बोर्ड को ऐसे आंकड़े और अन्य जानकारी प्रदान करेगा जो योजना के संचालन और वित्तपोषण के संबंध में उचित रूप से आवश्यक हो।

(6) यदि कोई पंजीकृत नियोक्ता बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर उपखंड (I) के तहत उससे देय भुगतान करने में विफल रहता है, तो सचिव पंजीकृत नियोक्ता को इस आशय का नोटिस देगा कि जब तक वह नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर अपने बकाया का भुगतान नहीं करता है, तब तक उसे पंजीकृत श्रमिकों की आपूर्ति निलंबित कर दी जाएगी।नोटिस की अवधि समाप्त होने पर सचिव चूक करने वाले पंजीकृत नियोक्ता को पंजीकृत श्रमिकों की आपूर्ति को तब तक निलंबित कर देगा जब तक कि वह अपने बकाया का भुगतान नहीं कर देता।

43. भविष्य निधि और उपदानः-

(1) बोर्ड पंजीकृत श्रमिकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि प्रदान करने वाले नियम बनाएगा और उनका संचालन करेगा।नियम योगदान की दर, भुगतान की विधि और ऐसे अन्य मामलों के लिए प्रावधान करेंगे जो आवश्यक माने जाएं ताकि योगदान की दर एक पंजीकृत कर्मचारी के वेतन के 6.5 प्रतिशत से कम न हो और ऐसे वेतन के 8 प्रतिशत से अधिक न हो।

बशर्ते कि नियम बनाए जाने तक बोर्ड के लिए योगदान की दर और उसके भुगतान की विधि और विधि तय करना विधिसम्मत होगा।

(क) अंशदायी भविष्य निधि के लिए नियम तैयार करते समय बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के समय-समय पर संशोधित प्रावधानों और किसी भी प्रतिष्ठान के लिए उसके तहत बनाई गई योजनाओं पर विचार करेगा।

(2) बोर्ड पंजीकृत श्रमिकों को उपदान के भुगतान के लिए नियम बनाएगा।

(2क) पंजीकृत श्रमिकों को उपदान के भुगतान के लिए नियम तैयार करने में, बोर्ड समय-समय पर संशोधित उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों को ध्यान में रखेगा।

(3) बोर्ड द्वारा बनाए गए भविष्य निधि और उपदान के नियम राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन होंगे।

7. श्री कामा का पहला तर्क कि 1970 की योजना, जहां तक यह रासायनिक उत्पादों के निर्माण के कारखाने में रोजगार का प्रावधान करती है, 1969 के अधिनियम की अनुसूची के अधिकार क्षेत्र अधिकारातीत है, को खारिज करना होगा।हम प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता से सहमत हैं कि अधिनियम की अनुसूची का खंड 5 एक अवशिष्ट खंड है जो अनुसूची में किसी अन्य प्रविष्टि के दायरे में नहीं आने वाले श्रमिकों द्वारा किए गए लोडिंग, अनलोडिंग आदि के संबंध में कारखानों में रोजगार प्रदान करेगा।मान लीजिए, कारखानों में पेट्रो रसायनों का निर्माण अनुसूची में प्रविष्टि 4 सहित किसी अन्य प्रविष्टि के दायरे में नहीं आता है।इस कारण से, हमारा विचार है कि कारखानों में पेट्रो रसायनों के निर्माण से संबंधित 1970 की योजना के प्रावधान अवशिष्ट प्रविष्टि यानी 1969 अधिनियम की अनुसूची की मद 5 के दायरे में होंगे। ऐसा होने के कारण, 1970 की योजना का कोई भी हिस्सा 1969 के अधिनियम के अधिकार क्षेत्र अधिकारातीत नहीं है।

8. अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता की दूसरी प्रस्तुति को भी इस कारण से अस्वीकार किया जाना चाहिए कि 1970 की योजना का खंड 2 (l) (t) 1969 के अधिनियम की खंड 1 (4A) तालिका कॉलम 4 आइटम 5 के अंतर्गत आता है। यह स्पष्ट है कि "उर्वरकों सहित उत्पाद" अभिव्यक्ति "उर्वरकों सहित रासायनिक उत्पादों" की तुलना में व्यापक है।1969 के अधिनियम की शब्दावली विवादित 1970 की योजना

की शब्दावली से व्यापक होने के कारण, स्पष्ट रूप से 1970 की योजना जब कारखानों में निर्मित "रासायनिक उत्पादों" की बात करती है और 1969 के अधिनियम की अनुसूची में प्रविष्टि 5 द्वारा कवर की जाती है, तो यह अभिव्यक्ति "उर्वरकों सहित उत्पाद" होगी।

9. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कामा ने आगे कहा कि अपीलकर्ता कथित रूप से रासायनिक उत्पादों के बजाय पेट्रोकेमिकल उत्पादों का निर्माण करता है, जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने यह कहते हुए सही ढंग से खारिज कर दिया है कि "पेट्रो रासायनिक उत्पाद" जीनस "रासायनिक उत्पादों" की एक प्रजाति होगी।वास्तव में, अपीलकर्ता ने स्वीकार किया है कि वह पॉलीस्टीरिन (दाने) का निर्माण करता है। पॉलीस्टीरिन को बदले में एक सस्ते और कठोर प्लास्टिक के रूप में वर्णित किया गया है जो एक विनाइल बहुलक है।रसायन और पेट्रो रसायन विभाग द्वारा बनाई गई जे. जे. पंचवर्षीय योजना में रसायनों और पेट्रो रसायनों पर कार्य समूह की रिपोर्ट में 2007-2008 से 2011-2012 तक कहा गया हैः-

> "जे. पेट्रोकेमिकल्स विभिन्न रासायनिक यौगिकों से प्राप्त होते हैं।मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन।ये हाइड्रोकार्बन कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होते हैं।कच्चे तेल 1 के आसवन द्वारा उत्पादित विभिन्न अंशों में, पेट्रोलियम गैसें, नाफ्था, मिट्टी का तेल और गैस तेल पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए मुख्य फ़ीड स्टॉक हैं।प्राकृतिक गैस से प्राप्त ईथेन और प्राकृतिक गैस तरल पदार्थ पेट्रोकेमिकल उद्योग में उपयोग किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खाद्य भंडार हैं।ओलेफिन (एथिलीन, प्रोपलीन और बुटाडीन) और सुगंध (बेंजीन, टोल्यून और

ज़ाइलीन) प्रमुख निर्माण खंड हैं जिनसे अधिकांश पेट्रोकेमिकल का उत्पादन किया जाता है।

2. पेट्रोकेमिकल विनिर्माण में दरार या सुधार संचालन द्वारा निर्माण खंडों का निर्माण शामिल है; निर्माण खंडों को फाइबर इंटररेडिएट्स (एक्रिलोनाइट्राइल, कैप्रोलैक्टम, डाइमिथाइल टेरेफ्थेलेट/शुद्ध टेरेफ्थेलिक एसिड, मोनो एथिलीन ग्लाइकोल) जैसे मध्यवर्ती में परिवर्तित करना; पूर्ववर्ती (स्टाइरीन, एथिलीन डाइक्लोराइड, विनील क्लोराइड मोनोमर आदि)। और अन्य रासायनिक मध्यवर्तीःसिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, इलास्टोमर्स, अन्य रसायनों का उत्पादन और उपभोक्ता और औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन के लिए प्लास्टिक का प्रसंस्करण।

10. उपरोक्त रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि न केवल विभिन्न रासायनिक यौगिकों से प्राप्त पेट्रो रसायन हैं, बल्कि यह भी कि पेट्रो रासायनिक निर्माण में अन्य चीजों के अलावा प्लास्टिक का उत्पादन शामिल है।वास्तव में, अधिनियम की खंड 13 के तहत नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा दी गई एक रिपोर्ट में, अधिकृत अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचेः

"इन परिस्थितियों में, मेरी राय है कि पॉलीस्टीरिन उत्पादन एक पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है, बल्कि यह एक रासायनिक या रासायनिक उत्पाद है।एक पल के लिए अगर यह स्वीकार किया जाता है कि कंपनी एक पेट्रोकेमिकल कंपनी है और पेट्रोकेमिकल का उत्पादन करती है, भले ही पेट्रोकेमिकल भी रसायनों में से एक है और इसलिए रासायनिक उत्पादन को स्वीकार नहीं करने का कोई कारण नहीं देखा जाता है और माथाडी अधिनियम और योजना लागू नहीं होती है।

आखिरकार पेट्रोकेमिकल रसायन हैं।यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि माथाडी अधिनियम और योजना को लागू करते समय पेट्रोकेमिकल्स को छोड़ दिया जाना चाहिए।इन परिस्थितियों में, मैं अपना निर्णय दे रहा हूं कि कंपनी का उपरोक्त बिंदु मान्य नहीं है और इसलिए माथाडी अधिनियम और योजना कंपनी पर लागू होती है।"

11. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा अपने दिनांक 1 के आदेश में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पेट्रो-रासायनिक उत्पाद रासायनिक उत्पादों की एक प्रजाति हैं और अपीलकर्ता रासायनिक उत्पादों का निर्माण करता है, इसे विकृत नहीं कहा जा सकता है।हमें नहीं भूलना चाहिए।कि उच्च न्यायालय रिट याचिका को खारिज करने में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग कर रहा था जो सरकार के समक्ष विवाद के गुण-दोष पर नहीं जाएगा, बल्कि केवल विकृति पर जाएगा-कि समान शक्ति के साथ निवेश किया गया कोई भी उचित व्यक्ति संभवतः सरकार द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है।अन्यथा भी, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम एक कल्याणकारी कानून के साथ काम कर रहे हैं जिसका प्राथमिक उद्देश्य दैनिक मजदूरों के रोजगार के लिए पर्याप्त रोजगार और बेहतर नियम और शर्तें प्रदान करना है, और उनके सामान्य कल्याण के लिए प्रदान करना है, जिसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय शामिल हैं, और उन्हें भविष्य निधि और उपदान सहित विभिन्न अन्य सुविधाएं प्रदान करना है।इसलिए अनावश्यक बाल-विभाजन में लिप्त तर्कों को हाथ से निकाल देना आवश्यक है।

12. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील द्वारा एक अन्य निवेदन यह है कि 1970 की योजना किराने के बाजारों या दुकानों से

संबंधित है जैसा कि इसके शीर्षक से पता चलता है और इसलिए 1969 के अधिनियम की खंड 4 (1) (बी) के अभ्यास का पालन किए बिना कारखानों में निर्मित पेट्रोकेमिकल्स को इसके दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता है। इस तर्क को फिर से इस कारण से खारिज किया जाना चाहिए कि अधिनियम की खंड 3 और 4 दोनों एक ऐसी योजना का उल्लेख करती हैं जो "किसी भी अनुसूचित रोजगार या रोजगार में" (1969 अधिनियम की खंड 3 (1) के अनुसार) असुरक्षित श्रमिकों के पंजीकरण का प्रावधान करती है।इसके अलावा, 1969 के अधिनियम की खंड 4 (1) यह भी स्पष्ट करती है कि राज्य सरकार किसी भी अनुसूचित रोजगार या अनुसूचित रोजगारों के समूह के लिए एक या अधिक योजनाएं बना सकती है।इन प्रावधानों को पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि एक समग्र योजना हो सकती है जो विभिन्न रोजगारों को अपने दायरे में लेती है जो 1969 के अधिनियम की अनुसूची की एक से अधिक प्रविष्टियों में निहित हो सकते हैं। ऐसा होने पर, यह स्पष्ट है कि केवल एक विशेष समग्र योजना को किराने का बाजार या दुकान योजना के रूप में नामित करने से मामला आगे नहीं बढ़ता है।यह स्पष्ट है कि वर्तमान योजना विशेष रूप से 1969 के अधिनियम की अनुसूची में प्रविष्टि 5 द्वारा कवर किए गए रासायनिक उत्पादों का निर्माण करने वाले अपने केन कारखानों के भीतर लेती है, और इसलिए यह एक ऐसी योजना होगी जो विभिन्न अनुसूचित रोजगारों और/या अनुसूचित रोजगारों के एक समूह में असुरक्षित श्रमिकों के पंजीकरण का प्रावधान करती है।इस मामले में, यह स्पष्ट है कि 1970 की योजना के किराना बाजार या दुकानों की योजना के रूप में नामकरण पर आधारित हमला विफल होना चाहिए।

13. हम प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता से भी सहमत हैं कि 1969 के अधिनियम की खंड 2 (4), जो "स्थापना" को परिभाषित करती है, में न केवल कोई भी स्थान या परिसर शामिल होगा जिसमें पेट्रो रसायनों का निर्माण किया जा रहा है,

बल्कि इसके परिसर भी शामिल होंगे, जिसमें कारखाने के द्वार से परे बल्कि कारखाने के परिसर के भीतर किया गया परिवहन शामिल होगा।यह मामला होने के कारण, यह सामान्य आधार है कि कर्मचारी आवश्यक हैं और अपीलकर्ता द्वारा अपीलकर्ता के उत्पादों को अपीलकर्ता के खरीदारों द्वारा प्रदान किए गए वाहनों पर लोड करने के लिए उपयोग किया जा रहा है।यह टाइल का मामला होने के नाते, कोई भी तर्क कि कारखानों की विनिर्माण गतिविधियाँ मशीनीकृत हैं और हाथ से श्रम की कोई आवश्यकता नहीं है, हाथ में मामले के लिए कोई सामग्री नहीं होगी।

14. यह न्यायालय,।बॉम्बे हाई कोर्ट के एक पूर्ण पीठ के फैसले को मंजूरी देते हुए, भुवाल्का स्टील मामले में 1969 के अधिनियम की खंड 2 (11) में आने वाली "असुरक्षित श्रमिक" अभिव्यक्ति की व्याख्या की गई है, जिसका अर्थ है प्रत्येक शारीरिक कार्यकर्ता जो किसी भी अनुसूचित रोजगार में लगा हुआ है या लगाया जाना है, चाहे वह अन्य श्रम कानूनों द्वारा संरक्षित हो या नहीं।इस न्यायालय ने 1969 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों को निम्नलिखित शब्दों में संदर्भित कियाः

> "उद्देश्यों और कारणों के विवरण में उल्लेख किया गया है कि समिति द्वारा 17.11.1967 पर सरकार को रिपोर्ट दी गई थी।उस रिपोर्ट में, यह उल्लेख किया गया था कि माथाड़ी, हमाल, बंदरगाहों में कार्यरत आकस्मिक श्रमिक, लोखंडी जत्था कार्यकर्ता, नमक पैन कार्यकर्ता और अन्य शारीरिक कार्यकर्ता जैसे व्यवसायों में लगे व्यक्ति ज्यादातर निश्चित परिसरों के बाहर खुले में काम करते हैं और ज्यादातर कई मामलों में पीस-रेट प्रणाली पर काम करते हैं।उन्हें सीधे नौकरी नहीं दी जाती है, लेकिन जब भी काम होता है तो वे या तो मुकदुम या टोलीवाला या गिरोह द्वारा से काम करते हैं और वे एक ही दिन

अलग-अलग नियोक्ताओं के लिए भी काम करते हैं।काम की मात्रा हमेशा स्थिर नहीं होती है।काम की विशिष्ट प्रकृति, इसकी विविधता, रोजगार के अनिश्चित साधनों और भुगतान की प्रणाली और इस वर्ग के श्रम के शोषण की विशेष संवेदनशीलता को देखते हुए, समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि ऐसे श्रमिकों पर विभिन्न श्रम कानूनों का लागू होना अव्यवहारिक था और मौजूदा श्रम कानूनों में संशोधन करके उनके काम करने और अन्य शर्तों का विनियमन संभव नहीं था।इसलिए, समिति ने सिफारिश की कि ऐसे असुरक्षित श्रमिकों के काम करने और रोजगार की स्थितियों को एक विशेष अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में आगे उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित कानून से प्रभावित हितों के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें करने के बाद और इन सभी सुझावों पर विचार करने और समिति की सिफारिशों की जांच करने के बाद, सरकार ने एक विधेयक लाने का फैसला किया था, जिसमें कुछ रोजगारों में कार्यरत मठड़ियों, हमलों और अन्य शारीरिक श्रमिकों के रोजगार को विनियमित करने, उनके रोजगार की शर्तों के लिए बेहतर प्रावधान करने, उनके कल्याण के लिए, स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों के लिए, जहां ऐसे रोजगारों के लिए उन उपायों की आवश्यकता होती है, ऐसी नौकरियों में ऐसे श्रमिकों की पर्याप्त आपूर्ति और पूर्ण और उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करने, ऐसी बेरोजगारी को रोकने के लिए और इस तरह के उद्देश्य के लिए इन रोजगारों के संबंध में बोर्डों की स्थापना का

प्रावधान करने (जहां आवश्यक हो) का प्रावधान किया गया है।(जोर दिया गया) "(पैरा 9 और 10 में)

15. 1969 के अधिनियम की खंड 2 (11) को सभी "असुरक्षित श्रमिकों", यानी किसी भी अनुसूचित रोजगार में लगे सभी शारीरिक श्रम को शामिल करने के लिए समझने के बाद, इस न्यायालय ने अन्य श्रम कानूनों के तहत संरक्षण की परवाह किए बिना कहाः-

> “फैसला देने से पहले, हमें इस तथ्य का उल्लेख करना चाहिए कि यह कानून, जो बहुत पहले 1969 में आया था, उसके विचार में उन गरीब श्रमिकों के बारे में है, जो न तो नियोक्ताओं के साथ सौदेबाजी करने की स्थिति में थे और न ही उनके पास मजबूर करने वाली सौदेबाजी की शक्ति थी।वे ज्यादातर टोलीवालों और मुकदमों पर निर्भर थे।उन्हें यकीन नहीं था कि उन्हें रोज काम मिलेगा।उन्हें यह भी यकीन नहीं था कि वे एक दिन में केवल एक नियोक्ता के लिए काम करेंगे।इन गरीब श्रमिकों के लिए हर दिन एक चुनौती थी।इसी विचार के साथ बोर्ड का गठन माथाडी अधिनियम की खंड 6 के तहत किया गया था। बोर्डों, योजनाओं आदि की रूपरेखा तैयार करने के लिए गहन विचार किए गए हैं। इन उदात्त विचारों के साथ यह अधिनियम अस्तित्व में आया।इन दिनों जब नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद। बांग्लादेश के यूनुस अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए व्यवसाय के खिलाफ सामाजिक व्यवसाय के सिद्धांत की वकालत कर रहे हैं, यह बेहतर होगा कि नियोक्ता अपने सामाजिक दायित्वों को महसूस कर

सकें, विशेष रूप से, समाज के वंचितों के लिए, उन श्रमिकों के लिए जिन्हें अधिनियम में आरोपित श्रमिक माना जाता है।"

16. सामाजिक विधान के इस टुकड़े के उद्देश्यों और कारणों से संकेत लेते हुए और इस तरह के विधान को व्यापक तरीके से समझने के प्रसिद्ध सिद्धांत से संकेत लेते हुए, जिसमें ऊपर उल्लिखित प्रकार के कल्याणकारी विधान के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, और इस तरह के उद्देश्य को कम करने के लिए नहीं, हम मानते हैं कि बॉम्बे उच्च न्यायालय को अपने तर्क में दोष नहीं दिया जा सकता है।यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 1970 की योजना का उद्देश्य न केवल नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को काम प्रदान करना है, बल्कि पंजीकृत श्रमिकों को सुविधाएं और लाभ प्रदान करना भी है।बोर्ड द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नियोक्ता से कुल वेतन बिल के 50 प्रतिशत से अधिक शुल्क वसूल कर कर्मचारियों को ये सुविधाएँ और लाभ प्रदान किए जाने हैं।हमें बताया गया है कि वर्तमान मामले में लेवी राशि 41 प्रतिशत है, जिसका उपयोग न केवल श्रमिकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए किया जाता है, बल्कि उन्हें 1970 की योजना के खंड 43 द्वारा प्रदान किए गए भविष्य निधि और उपदान जैसे अंतिम लाभ देने के लिए भी किया जाता है।

17. श्री कामा द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया कि धारा 2 (3), (7), (12) में निहित "नियोक्ता", "प्रमुख नियोक्ता" और "कर्मचारी" की परिभाषाओं को एक साथ पढ़ने पर, क्योंकि दोनों समितियां अपीलकर्ता कंपनी के खरीदारों के लिए और उनकी ओर से अनुबंध श्रम को नियोजित करने वाले ठेकेदार हैं, अपीलकर्ता कंपनी को "प्रमुख नियोक्ता" नहीं कहा जा सकता है जो 1969 के अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी है। हमें डर है कि यह विवाद अपीलार्थी कंपनी के मुँह में नहीं है।1969

के अधिनियम दिनांक 11.10.1996 के तहत पंजीकरण के लिए किए गए एक आवेदन द्वारा, कॉलम संख्या 7 में जो निम्नानुसार हैः-

> "7. क्या आप ठेकेदारों द्वारा से श्रमिकों को नियुक्त कर रहे हैं?यदि ऐसा है तो ठेकेदारों के नाम बताएँ।
>
> कंपनी ने विशेष रूप से दो सहकारी समितियों और एक अन्य ठेकेदार का उल्लेख किया है जिससे यह स्वीकार किया गया है कि उसने वास्तव में ठेकेदारों द्वारा से लगभग 30 श्रमिकों को नियुक्त किया है।

18. 1969 के अधिनियम के तहत एक नियोक्ता के रूप में पंजीकृत होने के लगभग 7 साल बाद, दिनांक 1.3.2003 के एक पत्र द्वारा, अपीलकर्ता कंपनी ने 1969 के अधिनियम में निहित रजिस्टर से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन किया। इसके बाद 10.5.2004 दिनांकित एक अभ्यावेदन आया जिसमें अपीलार्थी कंपनी ने कहाः-

> "कंपनी ने, हालांकि किसी भी माथाडी कर्मचारी को शामिल नहीं किया, अभियोजन पक्ष को देखते हुए, 11/10/1996 पर खुद को पंजीकृत किया, और पंजीकरण स.4516 जारी किया गया।पंजीकरण के बाद, कंपनी ने मामले को बंद करने के उद्देश्य से श्रम न्यायालय के समक्ष बोर्ड द्वारा दायर कार्यवाही में दोषी ठहराया।कंपनी प्रस्तुत करती है कि आई. डी. 1 तक पंजीकृत होने के बावजूद उसे कोई टोली आवंटित नहीं की गई थी, क्योंकि बोर्ड अच्छी तरह से जानता था कि कंपनी ने स्वयं ट्रकों को लोड करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया था और ट्रक चालकों/ग्राहकों ने लोडिंग कार्य के लिए समितियों के व्यक्तियों को नियुक्त किया था।कंपनी ने हमेशा की तरह अपना

व्यवसाय चलाया और जारी रखा और अपने उत्पादों को पूर्व-कार्य के आधार पर बेचा जिसमें ग्राहक ने पहले की तरह उन व्यक्तियों के साथ ट्रक भेजे जो लोडिंग के लिए सोसायटी से थे।"

19. इसी तरह उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में, पैराग्राफ 8 में अपीलकर्ता कंपनी की अपनी दलील यह है कि अपीलकर्ता ने बोर्ड के दबाव में यह मानते हुए प्रतिवादी संख्या 2 बोर्ड के साथ खुद को पंजीकृत किया कि अधिनियम और योजना लागू थी।इसे पंजीकरण No.4516 दिया गया था।इसके अलावा, कंपनी के खिलाफ अधिनियम के तहत कार्यवाही में उसने स्वीकार किया कि उसने खुद को पंजीकृत नहीं करने के लिए दोषी ठहराया।यह हमारे सामने तथ्यों की स्थिति होने के कारण, हम राज्य सरकार के दिनांकित 24.6.2008 के आदेश में दिए गए निष्कर्ष को गलत भी नहीं बता सकते, विकृत होने की तो बात ही छोड़िए।जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपने आदेश के पैराग्राफ 6 में, राज्य सरकार विशेष रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कंपनी में माथाडी का काम दो सहकारी समितियों द्वारा किया गया था, जिन्होंने श्रमिकों को नियुक्त करके काम किया था और अपीलकर्ता कंपनी द्वारा मुआवजा प्राप्त किया था।इस मामले में, श्री कामा के इस तर्क के लिए कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है कि यह अपीलकर्ता के खरीदार हैं न कि अपीलकर्ता कंपनी जो अधिनियम के तहत प्रमुख नियोक्ता है।

20. श्री काम के एक अन्य तर्क पर ध्यान देने की आवश्यकता है।श्री कामा ने हमारे समक्ष तर्क दिया कि 1969 का अधिनियम अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के साथ असंगत होने के कारण उक्त अधिनियम के प्रतिकूल होगा और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत अमान्य होगा।उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई आधार नहीं

उठाया गया था या तर्क नहीं दिया गया था, लेकिन कहा कि सर्वोच्च न्यायालय उन्हें इस याचिका को उठाने की अनुमति दे क्योंकि यह विशुद्ध रूप से कानून का सवाल है। हमें डर है कि यह इस कारण से संभव नहीं है कि भले ही श्री कामा ने यह कहना सही हो कि 1970 का केंद्रीय संसदीय अधिनियम 1969 के राज्य अधिनियम को अनिवार्य रूप से निरस्त कर देगा, फिर भी उक्त अधिनियम की खंड 30 (1) में प्रावधान है कि 1970 के अधिनियम के प्रावधानों के 1969 के राज्य अधिनियम के साथ कथित रूप से असंगत होने के बावजूद, फिर भी यदि किसी प्रतिष्ठान में नियोजित अनुबंध श्रम उन लाभों के हकदार हैं जो उनके लिए 1970 के अधिनियम के तहत अधिक अनुकूल हैं, तो अनुबंध श्रम अधिक अनुकूल लाभों का हकदार बना रहेगा, इसके बावजूद कि वे केंद्रीय संसदीय अधिनियम के तहत अन्य मामलों के संबंध में भी लाभ प्राप्त करते हैं। यह मामला होने के कारण, रिट याचिकाकर्ता पर यह दायित्व था कि वह न केवल तिरस्कार और निहित निरसन की याचिका पर विचार करे, बल्कि एक तथ्य के रूप में यह भी बताए कि 1969 के राज्य अधिनियम के तहत श्रमिक जो कुछ पाने के हकदार होंगे, वह उतना फायदेमंद नहीं होगा जितना कि वे 1970 के केंद्रीय अधिनियम के तहत पाने के हकदार होंगे।यह तब प्रत्यर्थी बोर्ड को इस तथ्यात्मक कथन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अवसर देगा।उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में इस आशय का कोई अनुरोध नहीं होने के कारण, यह स्पष्ट है कि हमारे लिए श्री कामा के तिरस्कार और निहित निरसन पर तर्क में जाने के अनुरोध मान लेना संभव नहीं है।

21. तदनुसार, यह अपील खारिज कर दी जाती है।

सिविल अपील No.9999/2010

22. इस अपील में, तथ्य यह है कि अपीलकर्ता कंपनी शीतल पेय का निर्माण कर रही है जो वातित पानी और बोतलबंद पानी है।अधिनियम की खंड 5 के तहत

बनाए गए राज्य सरकार के दिनांक 18.8.2008 के आदेश ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः-

> “5. सरकार ने सभी मामले के दस्तावेजों का अध्ययन किया है और उपरोक्त परिस्थितियों पर विचार किया है।मामले के सभी पहलुओं की जांच करने के बाद सरकार निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंची हैः-
>
> (क) कंपनी पेय जल और विभिन्न प्रकार के पेय जैसे पेप्सी, मिरिंडा और सेवन-अप का उत्पादन करती है।
>
> (ख) उक्त उत्पादों में कंपनी कच्चे माल के रूप में उपयोग करती है जैसे कि चीनी, कास्टिक सोडा, कार्बोनिक एसिड; एस्कॉर्बिक एसिड; कॉफिन, सीक्वेस्टर्स एजेंट, बफरिंग; कार्मेल वाटर, इमल्सीफाइंग और स्टेबिलाइजिंग।
>
> (ग) "पेय" खाद्य उत्पादों के पदार्थों में से एक है;
>
> (घ) "पेय" एक किराने का उत्पाद है;
>
> (ई) कच्चा माल जिससे वे हैं
>
> उत्पादित भी मुख्य रूप से उपभोग्य खाद्य उत्पाद हैं।
>
> (च) उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल और निर्मित उत्पाद दोनों ही उपभोग्य खाद्य उत्पाद (तरल और ठोस) हैं।
>
> (छ) माथाडी अधिनियम और उसके तहत प्रसिद्ध योजना लाभकारी और परोपकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं और इसका उद्देश्य किराने के बाजार और दुकानों के असुरक्षित श्रमिकों (रोजगार और कल्याण

का विनियमन) योजना, 1970 में प्रदान किए गए किराने के बाजार उत्पादों का निर्माण करने वाली कंपनियों पर लागू करना है।

6. उपरोक्त परिस्थितियों में, राज्य इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि किराने का बाजार और दुकान कर्मचारी बोर्ड की योजना कंपनी पर लागू होती है।

7. कंपनी पेय पदार्थों और पीने के पानी के उत्पादों में लगी हुई है और इसके परिणामस्वरूप माथाडी की प्रकृति में कच्चे माल की लोडिंग, अनलोडिंग, स्टैकिंग, ले जाने की स्थापना जैसे कार्यों को जारी रखती है।उक्त कार्य किराना बोर्ड पर्यवेक्षक की देखरेख में ठेकेदार मेसर्स एम. एम. पाटिल के 49 श्रमिकों द्वारा किया गया था।उक्त श्रमिक, अपने वेतन को छोड़कर, पी. एफ. योगदान, छुट्टियों का भुगतान, घर का किराया, श्रमिकों के मुआवजे, बोनस और अन्य चिकित्सा लाभों से वंचित थे।इन परिस्थितियों में, महाराष्ट्र माथाडी, हमाल और अन्य मैनुअल श्रमिक (रोजगार और कल्याण का विनियमन) अधिनियम, 1969 और किराने का बाजार या दुकानें असुरक्षित श्रमिक (रोजगार और कल्याण का विनियमन) योजना, 1970 के प्रावधान आपके प्रतिष्ठान पर लागू होते हैं।इसलिए, माथाडी अधिनियम की खंड 5 के प्रावधानों के तहत आपके द्वारा सरकार को किए गए आवेदन को खारिज कर दिया जाता है।"

23. उक्त आदेश के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय में दायर एक रिट याचिका विफल हो गई।उच्च न्यायालय ने याचिका को इस प्रकार खारिज कर दियाः-

“दूसरा निवेदन यह है कि याचिकाकर्ता पेप्सी, मिरिंडा, सेवन-अप आदि जैसे सॉफ्ट ड्रिंक का निर्माण कर रहे हैं और यह किराने का सामान नहीं है।इस अदालत के समक्ष यह विवादित नहीं है कि इन शीतल पेय पदार्थों की निर्माण प्रक्रिया में याचिकाकर्ता चीनी, कार्बोनिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ताबूत, सीक्वेस्ट्रेट्स एजेंटों का उपयोग कर रहे हैं। याचिकाकर्ता बोतलों को साफ करने के लिए कास्टिक सोडा का उपयोग कर रहे हैं।लेकिन हम पाते हैं कि ये शीतल पेय व्यक्तियों को तरोताजा करने और थकने पर उन्हें ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रदान किए जाते हैं।चीनी या कार्बनिक हाइड्राइड जैसी वस्तुएँ ऊर्जा प्रदान करती हैं।यह भी विवादित नहीं है कि निर्माण प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली ये सभी वस्तुएं किराने की वस्तुएं हैं और तदनुसार राज्य सरकार ने यह भी टिप्पणी की है कि ये किराने की वस्तुएं हैं।इसके अलावा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने "किराने" का अर्थ दिया है।उक्त शब्दकोश के अनुसार "किराने" का अर्थ है किराने की दुकान या सुपर-मार्केट में भोजन की वस्तुएँ।

आजकल सभी सॉफ्ट ड्रिंक किराने की दुकानों और सुपरमार्केट में उपलब्ध हैं।वे भोजन की वस्तुएँ हैं और इसलिए, वे सभी किराने की वस्तुएँ हैं।इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह विवादित नहीं है कि सभी विनिर्माण प्रक्रिया में, लोडिंग और अनलोडिंग गतिविधियाँ की जाती हैं, जो कि माथाडी कामगारा की गतिविधियाँ हैं।हमें उठाए गए विवादों में कोई सार नहीं मिलता है।रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।”

24. श्री गिरि, श्री कामा द्वारा उठाए गए प्रस्तुतिकरणों के अलावा, अपने विशेष तथ्यों पर प्रस्तुत करते हैं कि कच्चे माल को ध्यान में रखना गलत है जो अंततः तैयार उत्पादों के निर्माण में चला गया और यह कहना कि उक्त कच्चा माल किराने का सामान है, इसलिए अंतिम उत्पाद को भी "किराने का सामान" बना देगा।उन्होंने आगे तर्क दिया कि "किराने" शब्द में केवल वही वस्तुएँ शामिल होंगी जो घरों में तेल, अनाज आदि जैसी दैनिक आवश्यकताओं के रूप में आवश्यक हैं, और ऐसा नहीं होने पर, शीतल पेय और बोतलबंद पानी "किराने" शब्द के बाहर होगा।उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जब वर्ष 1983 में अधिनियम का विस्तार अपीलकर्ता कंपनी के कारखाने तक किया गया था, आज जो भी स्थिति हो, 1983 में स्थिति स्पष्ट थी और जाहिर है कि अपीलकर्ता कंपनी द्वारा निर्मित वस्तुएं "किराने" की अभिव्यक्ति के भीतर नहीं आती थीं जैसा कि 1983 में समझा गया था।

25. बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने इन सभी तर्कों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि "किराना" अभिव्यक्ति खाद्य और पेय की सभी वस्तुओं को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक थी जो अनिवार्य रूप से अपीलकर्ता कंपनी के उत्पादों में शामिल होंगी।उन्होंने निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 1969 के अधिनियम जैसे लाभकारी अधिनियम का अर्थ निकालने पर अपने तर्क को दोहराया और कहा कि यह मानते हुए कि "किराने" शब्द का अर्थ संकीर्ण है, जाहिर है कि व्यापक अर्थ को ध्यान में रखा जाना चाहिए।इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि 1983 में जो भी स्थिति थी, 2005 में कारणदर्शक नोटिस के स्तर पर और 2008 में राज्य सरकार के आदेश की तारीख तक अपीलकर्ता कंपनी द्वारा निर्मित शीतल पेय और बोतलबंद पानी दोनों निश्चित रूप से मध्यम वर्ग और समाज के अमीर वर्गों के बीच घरेलू वस्तुएं थीं।

26. ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश के 9वें संस्करण में "किराने" की परिभाषा इस प्रकार हैः-

> “किराना-(किराने की दुकान) एक दुकान/दुकान जो भोजन और घर में उपयोग की जाने वाली अन्य चीजें बेचती है।अमेरिकी अंग्रेजी में 'किराने की दुकान' का उपयोग अक्सर सुपरमार्केट के लिए किया जाता है।2. किराने का सामान-भोजन और अन्य सामान जो किसी किराने वाले या सुपरमार्केट में बेचे जाते हैं।” हमें कॉलिन्स इंग्लिश डिक्शनरी, थर्ड एडिशन में एक उपयोगी परिभाषा भी मिलती है-"किराने का सामान-माल, विशेष रूप से।खाद्य पदार्थ, एक किराने वाले द्वारा बेचे जाते हैं। "

27. 2005 में जब अधिनियम को अपीलकर्ता कंपनी पर लागू करने की मांग की गई थी, तब "किराना" शब्द में अपीलकर्ता कंपनी द्वारा निर्मित शीतल पेय और बोतलबंद पानी को मध्यम वर्ग और समाज के अमीर वर्गों के बीच दैनिक घरेलू सामान के रूप में शामिल किया गया था, जिसका श्री गिरि ने गंभीरता से विरोध नहीं किया था।यह तर्क कि जिस तारीख को अधिनियम को उस क्षेत्र में विस्तारित किया गया था जिसमें अपीलकर्ता कंपनी का कारखाना स्थित था, उस तारीख को हमें "किराने" शब्द का अर्थ खोजना चाहिए, कानून में गलत है।इस न्यायालय ने वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक और अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण चोपड़ा और अन्य, 1962 (3) एस. सी. आर. 146 में, जब श्री गिरि द्वारा दिए गए समान तर्क का सामना किया गया, तो उक्त तर्क को निम्नलिखित शब्दों में खारिज कर दियाः

> “कानूनी स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैःकोक द्वारा निर्धारित समकालीन व्याख्या सिद्धांत को प्राचीन कानूनों को समझने

के लिए लागू किया गया था, लेकिन उन अधिनियमों की व्याख्या करने के लिए नहीं जो तुलनात्मक रूप से लागू होते हैं। आधुनिक। व्याख्या के तरीके में इस बदलाव का एक अच्छा कारण है।निर्माण का मूल नियम वही है चाहे न्यायालय को किसी प्राचीन अधिनियम या आधुनिक अधिनियम के प्रावधान का अर्थ निकालने के लिए कहा जाए, अर्थात् विधानमंडल का व्यक्त इरादा क्या है।एक स्थिर समाज में काम करने वाले एक विधायी निकाय को शायद यह श्रेय देना मुश्किल है कि इसका इरादा काफी विस्तार के संदर्भ में था ताकि उपयोग किए गए वाक्यांश द्वारा समझे गए भविष्य के विकास को अपने दायरे में लिया जा सके।अपने इरादे को केवल उन परिस्थितियों तक सीमित रखना अधिक उचित है जब कानून बनाया गया था। लेकिन एक आधुनिक प्रगतिशील समाज में एक विधानमंडल के इरादे को उस समय उपयोग किए गए शब्द के अर्थ तक सीमित रखना अनुचित होगा जब कानून बनाया गया था, एक आधुनिक विधानमंडल के लिए एक ऐसे समाज को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाना जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, यह माना जाना चाहिए कि एक विस्तारित अर्थ के बारे में जागरूक होना चाहिए जो समय के साथ और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक और मानव गतिविधि के अन्य क्षेत्रों में लाए गए क्रांतिकारी परिवर्तनों के साथ आकर्षित हो सकता है।वास्तव में, जब तक कोई विपरीत इरादा प्रकट नहीं होता है, तब तक नए तथ्यों और स्थितियों को लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्दों की व्याख्या की जानी चाहिए, यदि शब्द उन्हें समझने में सक्षम हैं।इसलिए हम उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों से

सहमत नहीं हो सकते हैं कि अधिनियम में (156,157 पर) "टेलीग्राफ लाइन" शब्द का अर्थ निकालने में समकालीन व्याख्या का उपयोग किया जा सकता है।

28. इस प्रकार हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय राज्य सरकार के दिनांक 1 के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करने और अपीलकर्ता कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने में आत्यन्तिक रूप सही था। सिविल अपील स.10000/2010 में दिए गए समान कारणों के लिए, हम इस अपील को भी अस्वीकार करते हैं।तदनुसार, अपील को खारिज कर दिया जाता है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।

कल्पना के. त्रिपाठी

याचिका खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिएए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।